शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 43 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 30 – 6 नवम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या सरकार ऑपरेशन लोटस के संकट पर आ पहुंची है?

- कर्ज और आपदा सहायता के आंकड़े पर छिड़ा घमासान
- मुकेश अग्निहोत्री और जगत सिंह नेगी का प्रदेश भाजपा पर बड़ा आरोप
- भाजपा के इशारे पर केंद्र ने रोके 4950 करोड़
- आर.टी.आई. के माध्यम से बिन्दल का सरकार पर दस माह में 113 00 कर्ज लेने का खुलासा
- सुक्खू की गैर हाजिरी सरकार और विपक्ष का सामना सरकार के लिए हो सकता है घातक

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार दस माह में 11300 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और यदि कर्ज लेने की यही गति जारी रही तो पांच साल में इस सरकार के नाम 60,000 करोड़ के कर्ज का रिकॉर्ड बन जायेगा। यह आरोप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने आर.टी.आई. के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर लगाया है। दूसरी ओर सुक्खू सरकार में उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राजस्व एवं

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

ने एक संयुक्त ब्यान में आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश भाजपा नेताओं के इशारे पर 4950 करोड़ की आपदा सहायता राशि रोक रखी है। इन मंत्रियों ने खुलासा किया है कि केन्द्र सरकार की ओर से टीमें प्रदेश में आपदा का आकलन करने आयी थी और प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त को 6746 करोड़ का पहले प्रस्ताव सहायता के लिए भेजा था। इसके बाद 10 अक्तूबर को 9900 करोड़ की सहायता का दूसरा प्रस्ताव भेजा था। इस तरह 4950 करोड़ प्रस्ताव का 50% प्रदेश का हक बनता था जो जारी नहीं किया गया है और इसके लिये प्रदेश भाजपा नेतृत्व जिम्मेदार है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के नेता सुक्खू सरकार की गारंटीयों को पांच राज्यों के चुनाव में मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा में इन गारंटीयों की सूची दिखाते हुए आरोप लगाया है कि हिमाचल में एक वर्ष में इस पर अमल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है न ही किसी किसान से 100 रूपये लीटर दूध खरीद गया है और न ही 2 रूपये किलो गोबर। गारंटीयों के नाम पर प्रदेश सरकार का पक्ष बहुत कमजोर है और शायद इसीलिये इस सरकार का कोई भी मंत्री इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पाया है। यह बढ़ता कर्ज और गारंटीयों पर अमल की दिशा में कोई कदम न उठा पाना सुक्खू सरकार के लिए आने वाले दिनों में कई बड़े मुद्दे होंगे। क्योंकि इस समय भाजपा और कांग्रेस के लिए यह विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव अस्तित्व का सवाल बनने जा रहे हैं। इण्डिया गठबंधन बनने से पहले टूटने के संकेत देने लग गया है और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आज कांग्रेस ही मोदी – भाजपा के लिये सबसे बड़ी चुनौती है।

ऐसे में इस चुनौती को और कमजोर करने के लिए कांग्रेस की किसी सरकार को अस्थिर करने तक की रणनीति पर मोदी सरकार जा सकती है। भाजपा की इस संभावित रणनीति का आसान शिकार सुक्खू सरकार को माना जा रहा है। क्योंकि हिमाचल में जयराम सरकार पर सबसे बड़ा आरोप प्रदेश को कर्ज के गर्त में धकेलना लगा था। लेकिन आज भाजपा बाकायदा आर.टी.आई. के सहारे सुक्खू सरकार पर अपने से भी कई गुणा बड़ा कर्ज का ही आरोप लगा रही है। इस आरोप के अतिरिक्त मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में किसी न किसी बहाने टाइम निकालने के मुकाम पर सरकार को पहुंचा दिया गया है। इस समय अपनी बीमारी के कारण मुख्यमंत्री स्वयं फ्रन्ट पर आकर मोर्चा संभालने की स्थिति में नहीं है। संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव आम आदमी की जानकारी में आ चुका है।

शीर्ष प्रशासन जितना शुभचिन्तक इस सरकार का है उससे ज्यादा पूर्व सरकार का है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सलाहकारों ने कोई कदम नहीं उठाने दिया है। इस समय मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में पूरा प्रशासन अराजक हो गया है। सरकार का वित्तीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज लेने पर रोक लगने के हालात बनते जा रहे हैं। पूरी भाजपा शान्ता से लेकर बिन्दल तक सरकार पर आक्रामक हो चुकी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल सरकार को अपने ही भार से दम घुटने के मुकाम पर पहुंचा देगी। मुख्य संसदीय सचिवों के प्रकरण पर यदि लोस चुनाव से पहले कोई अदालती फैसला नहीं आता है तो गारंटीयों पर अमल न होना और कर्ज का बढ़ना बजट सत्र के मुख्य मुद्दे हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार के लिये बजट पारित करवाने तक का संकट खड़ा हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राजभवन में मनाया गया जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की

अध्यक्षता करते हुए कहा कि धर्म, जाति व क्षेत्रवाद की संकीर्णता को समाप्त करना ही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत-श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रहा है जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस को हर राज्य में मनाने की एक पहल की गई है।

शिव प्रताप शुक्ल ने इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के मूल निवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 की शक्तियों को समाप्त करने के बाद 31 अक्तूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख दो अलग केंद्र शासित राज्य बने।

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित राज्य की स्थापना से पूर्व कश्मीर की जनता व जन-जीवन पूर्णतया अस्त-व्यस्त था। वर्ष 2019 के बाद जम्मू व कश्मीर में केंद्र सरकार की मदद से अनेक नई व महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरी हुई हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है जिससे ये दोनों राज्य अब खुशहाली व समृद्धि की ओरअग्रसर हैं।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित राज्य के रूप में गठन से लद्दाख में चहुंमुखी विकास को गति मिली है। गत वर्षो में इस राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। देश का सीमावर्ती राज्य होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों व टनलों का निर्माण किया गया है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस राज्य में धार्मिक कट्रपंथियों के भय से आम जनजीवन भय, निराशा व अवसाद के कारण त्रस्त था वहां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकास व समृद्धि को बढ़ावा मिला है। अब राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए गए हैं। पर्यटकों के आवागमन से स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि हुई है।

कार्यक्रम में लद्दाख के सांस्कृतिक दल को उनके मनमोहक प्रस्तुति के लिए 51 हजार रूपए प्रदान किए। कश्मीर के नागरिक शुभदीप सिंह ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने से अपने परिवार व स्थानीय मुस्लिम परिवारों के साथ घटित मर्मस्पर्शी घटनाएं साझा कीं। राज्यपाल ने उपस्थित जन समूह तथा राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल तथा लेडी गर्वनर जानकी शुक्ल ने दोनो राज्यों के उपस्थित निवासियों को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और दोनों राज्यों के नागरिक उपस्थित थे।

दीपावली उत्साह का उत्सव इसे मिलजुल कर मनाएं: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ढली स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान में सभी बच्चों को दीपावली उत्सव के उपलक्ष्य में मिठाई वितरित कर उन्हें इस पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी।

राज्यपाल ने कहा कि दीवाली उत्साह का उत्सव है और इसे मिल-जुल कर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपावली उत्सव के माध्यम से हमें अपनी समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक यह दीपोत्सव बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत का संदेश देता है।

उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने आत्मबल व दृढ़ इच्छाशक्ति के बूते किसी भी तरह की शारीरिक चुनौतियों व प्रतिकूल परिस्थितियों को मात देकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत एक सामान्य व्यक्ति आलस्य, लापरवाही और बुरी आदतों के कारण समाज व परिवार पर बोझ ही होता है।

उन्होंने विद्यालय के छात्रों द्वारा बेहतर मंच संचालन की सराहना की तथा कहा कि ये सभी छात्र प्रतिभा सम्पन्न हैं और इनकी क्षमता को तराशने की आवश्यकता है।

मुख्याध्यापक धर्मपाल राणा ने राज्यपाल के आगमन पर उनका आभार व्यक्त किया तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर संस्थान के अध्यापक व प्रशिक्षक, रेडक्रॉस सोसायटी के स्वयंसेवी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

राजभवन में रामायण पाठ का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित

अखण्ड रामायण पाठ के पूर्ण होने पर हवन यज्ञ में पूर्णाहूति दी। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के अनुष्ठानों से आध्यात्मिक शांति, आपसी प्रेम व सौहार्द में वृद्धि होती है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की भी कामना की।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा सहित राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल

शिमला/शैल। भारतीय साहित्य व विज्ञान पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता है और हमारे विद्वानों को इस क्षेत्र में व्यापक शोध करने की आवश्यकता है। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर कही।

'आधुनिक भारत के प्रबुद्ध समाज-साहित्य और विज्ञान के संदर्भ' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विद्वान भाग ले रहे हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. राधाकृष्णन ने एक ऐसे शोध केंद्र के रूप में की थी जिसमें देश-विदेश के विद्वान मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शोध कार्य करते रहे हैं।

उन्होंने कहा कि साहित्य व विज्ञान के विकास तथा इनके संरक्षण में आधुनिक भारतीय प्रबुद्ध समाज जिनमें गुजराती वर्नाक्युलर सोसायटी, कर्नाटक विद्वावर्धक संघ, नागरी प्रचारणी सभा, उत्कल साहित्य समाज व असम साहित्य सभा की अहम भागीदारी रही है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण हर क्षेत्र में सम्पन्न भारत विश्व में ज्ञान व विज्ञान से प्राप्त समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, अध्यात्मिक श्रेष्ठता व सम्पन्नता के कारण बड़ी संख्या में विदेशी भारत की ओर आकृष्ट हुए। इतिहास लेखन की तमाम विसंगतियों के बावजूद हमारा गौरवमयी इतिहास अक्षुण रहा है। भारतीय ज्ञान-सृजन और उसके प्रचार-प्रसार में प्रबुद्ध समाज की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अब भारतवर्ष ने पुन: अपना गौरव हासिल कर विश्व में खोई प्रतिष्ठा को पुन: अर्जित किया है।

उन्होंने कहा कि मां, मातृभूमि तथा मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। यह चिंता का विषय है कि भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति विश्वभर में आस्था, श्रद्धा व विश्वास में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें अपनी नई पीढ़ी को विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण कर जीवन को अंधकार में धकेलने से सचेत करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि समस्त प्रबुद्ध समाज व सभी नागरिकों का दायित्व है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी सहभागिता दर्ज करवाकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश को सक्षम नेतृत्व प्राप्त है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पुन:स्थापित करने में सफल रहा है।

इस अवसर राज्यपाल ने पौधरोपण भी किया। उन्होंने प्रो. डम्बरूधन नाथ द्वारा लिखित पुस्तक 'निर्गुण भक्ति इन इस्टर्न इंडिया' का भी विमोचन किया।

सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, डॉ. अतुल कोठारी ने आजादी से पूर्व तथा उसके उपरांत भारत की समृद्ध संस्कृति तथा इतिहास पर किए गए कुठाराघात बारे तथ्यपूर्ण साक्ष्य व टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के चहुंमुखी विकास बारे विदेशी प्रख्यात इतिहासकारों ने हैरान करने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक प्रो. नागेश्वर राव ने संस्थान से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी।

संस्थान की अध्यक्ष प्रो. शशिप्रभा कुमार ने वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित किया।

इस अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल भाई कोठारी, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, अध्येता एवं कार्यक्रम संयोजक मेहरचंद नेगी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के डॉ. सिद्धार्थ सत्यार्थी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रटचा शर्मा

किन्नौर व लाहौल-स्पिति जिला के जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में जनजातीय

क्षेत्र किन्नौर व लाहौल- स्पिति जिला की 13 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने लियो से चांगो सड़क के निर्माण कार्य सहित इन क्षेत्रों की अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं से उन्हें अवगत करवाया।

राज्यपाल ने कहा कि 11 किलोमीटर लम्बी लियो से चांगो सड़क के निर्माण कार्य में गति लाने के लिए प्रदेश सरकार से सिफारिश करेंगे।

उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ की बहाली तथा सीमा सड़क संगठन को सड़क निर्माण कार्य सौंपने बारे अवगत करवाएंगे। इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को निर्बाध परिवहन सुविधा प्राप्त होगी तथा पर्यटकों को भी आवागमन से सम्बन्धित समस्याओं से निजात मिलेगी। सेना व अर्द्धसैनिक बलों के लिए भी यह लाभप्रद होगी।

उन्होंने कहा कि हाल ही में जनजातीय क्षेत्र का उनके दौरे का उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों तथा इस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों व समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना था। राज्यपाल ने किन्नौर तथा स्पिति घाटी के लोगों की आतिथ्य सत्कार भावना की भी सराहना की।

इंतकाल अदालतों में किया गया 31105 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। प्रदेश में इंतकाल के लम्बित मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने पहली बार अनूठी पहल करते हुए 30 व 31 अक्तूबर, 2023 को विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाया गया यह कदम प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इन इंतकाल अदालतों में प्रदेशभर में इंतकाल के लंबित 41907 मामलों में से 31105 का निपटारा कर दिया गया। दो दिनों के भीतर ही 74.22 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया, जो सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को इंगित करता है। बिलासपुर जिला में इन दो दिनों के दौरान सबसे अधिक 90.78 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया। यहां लंबित 1943 मामलों में से 1764 में इंतकाल दर्ज किये गए। किन्नौर जिला में 90.75 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ तथा यहां कुल लंबित 400 में से 363 मामलों में इंतकाल दर्ज किए गए जबकि ऊना जिला में 89.12 प्रतिशत मामलों में इंतकाल दर्ज हुए। यहां 3670 लंबित मामलों में से 3271 इंतकाल सत्यापित किए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि गुडगवर्नेंस के लिए गुड गवर्मेंट का होना आवश्यक है। प्रदेशभर में लंबित इंतकाल के मामलों से लोग बहुत परेशान थे और वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतकाल अदालतें लगाने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेशभर में आयोजित की गई इंतकाल अदालतों से आम आदमी लाभान्वित हुआ है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जा रहा है। जिला कांगड़ा निवासी मीना देवी ने दो दिवसीय विशेष इंतकाल अदालतों के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मामला वर्ष 1996 से लंबित था। लेकिन वर्तमान सरकार की इस पहल से वर्षों का काम चंद मिनटों में ही पूरा हो गया। वहीं ऊना निवासी गुरचरण सिंह ने कहा कि इस विशेष इंतकाल अदालत का लाभ उन्हें भी मिला है। काफी वर्ष पहले उन्होंने इंतकाल के लिए आवेदन किया था, जो काफी समय से लंबित था, लेकिन अब दोनों भाइयों के नाम पर इंतकाल सत्यापित हो गया है। मण्डी निवासी मनजीत ने भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस विशेष प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल दर्ज कराने के लिए काफी समय से उन्हें कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन मण्डी में लगी विशेष इंतकाल अदालत में चंद मिनटों में ही उनका काम पूर्ण हो गया। वहीं चम्बा निवासी देवेश वर्मा ने भी राज्य सरकार का विशेष इंतकाल अदालत के आयोजन के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया। वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है तथा उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटारा करने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह के प्रयास जारी रखेगी।

246 परिवारों को मकान के किराए के रूप में प्रदान की जा रही है वित्तीय सहायता

शिमला/शैल। प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान किराये के रूप में 74.25 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें बिलासपुर उपमण्डल के दो, घुमारवीं उपमण्डल के 44, झण्डुता उपमण्डल के 9 परिवार शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक इन परिवारों को किराये के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

झण्डुता निवासी निर्मला देवी ने बताया कि आपदा के दौरान उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया था तथा उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उन्हें पहले राहत शिविर में ठहराया गया तथा अब उन्हें किराये के मकान में शिफ्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मकान का किराया अदा करने के लिए उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है और राशन भी निःशुल्क ही प्रदान किया जा रहा है। वहीं बिलासपुर जिला निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि आपदा के दौरान उनके घर में दरारें आ गई थीं तथा घर रहने लायक नहीं रहा था। राज्य सरकार द्वारा अब उन्हें मकान का किराये अदा करने के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं जिसके कारण वे सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस मद्द के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

वहीं जिला कांगड़ा में 73 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनमें से 7 कांगड़ा उपमंडल, 13 ज्वाली, 24 नूरपुर, 11 धीरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराये के रूप में राज्य सरकार 21.90 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने जा रही है।

मण्डी जिला में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान का किराये प्रदान करने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। जिला के तहत थुनाग उपमंडल में 13, सरकाघाट उपमंडल में 75, धर्मपुर में 10, बालीचौकी में 8, जोगिन्द्रनगर में 9 तथा गोहर उपमंडल में 3 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार इन आपदा प्रभावित परिवारों को 35.40 लाख रूपये मकान किराये के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में संवेदनशील सरकार काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। यह मुख्यमंत्री की ही सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवन-यापन के ष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार ने अब तक इस तरह का कदम नहीं उठाया है जबकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रत्येक आपदा प्रभावित की पीड़ा को समझते हुए निर्णय ले रहे हैं। हर प्रभावित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

समाज की प्रगति और गुड गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका: गोकुल बुटेल

शिमला/शैल। प्रदेश के विकास में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर महत्वाकांक्षी एवं सार्थक बदलाव लाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गोकुल बुटेल ने यह जानकारी डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 5जी का उपयोग एवं क्षमता निर्माण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी।

गोकुल बुटेल ने कहा कि नागरिक सेवाओं का दायरा विस्तृत करने, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने तथा दक्षता बढ़ाने के लिए 5जी तकनीक अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा, स्वास्थ्य, निगरानी, कृषि, बागवानी सहित अन्य क्षेत्रों में उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिकी को सशद्द करने में बल मिलेगा बल्कि प्रदेश को आगामी 10 वर्षों में आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश विकास से बदलाव के नए दौर की ओर अग्रसर है तथा सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका इसमें सबसे अहम है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में 5जी तकनीक को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों को हरसम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। विभागों की कार्यप्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित की गई है। इसके साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर नागरिक सेवाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेटवर्क सेवाओं, आपसी समन्वय व प्रदेश में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के महत्त्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्थक भूमिका निभा सकता है।

सचिव, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन ने प्रदेश में 5जी के उपयोग और आधारभूत संरचना सृजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5जी सेवाओं के प्रसार और नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार हिमाचल परिमंडल दीपिका खोसला व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन नीरज कुमार ने 5जी से संबंधित क्षमता निर्माण के बारे में किए जा रहे प्रयासों एवं वस्तुस्थिति के बारे में अवगत करवाया।

इस अवसर पर 5जी तकनीक के उपयोग व प्रसार से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

सम्मेलन में निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस मुकेश रेपस्वाल, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपिस्थत थे।

हिम समाचार ऐप एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नें बताया कि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हिम समाचार ऐप अब ऐप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है और इसे आईओएस सॉफ्टवेयर पर भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह ऐप लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिससे वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह ऐप सूचना एवं जन संपर्क विभाग की एक पहल है। इस ऐप के माध्यम से लोग राज्य सरकार के निर्णयों, वीडियो सामग्री, विभागीय समाचार बुलेटिन और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐप हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया था। पहले यह ऐप्लिकेशन केवल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था और अब यह ऐप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है।

सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का गीत-संगीत एवं नाटकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए निजी सांस्कृतिक दलों को दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। स्क्रीनिंग में प्रस्तुति के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले सांस्कृतिक दलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश सहकारिता अधिनियम के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक निजी सांस्कृतिक दल में कम से कम चार महिला कलाकारों सहित कुल 11 कलाकार होने अनिवार्य हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सांस्कृतिक दल अपना आवेदन निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र., शिमला-171002 के कार्यालय में 04 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदनकर्ता सूचिबद्धता की शर्तें एवं आवेदन-पत्र को विभागीय वेबसाइट www.himachalpr.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रसंघ ने किया दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में सहयोग का आग्रह

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास सूद ने बताया कि दीपावली के पावन अवसर पर प्रसंघ प्रदेशवासियों की सुविधा के दृष्टिगत बाजार में अपनी शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाईयां उपलब्ध करवा रहा है। इनमें शुगर फ्री मिठाईयां और गिफ्ट पैक भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सभी मिठाईयां दुग्ध प्रसंघ प्रबंधन अपनी देख-रेख व पूर्ण निगरानी में तैयार करवाता है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि दीपावली के उपलक्ष्य में मिठाईयों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह ग्राहकों को पिछले वर्ष की दरों पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दुग्ध प्रसंघ द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

प्रबंध निदेशक ने प्रदेशवासियों से प्रसंघ की मिठाईयां तथा अन्य उत्पाद खरीदने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके।

संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कांग्रेस को अकेला ही चलना होगा

क्या विपक्षी एकता बनी रहेगी यह सवाल शैल पहले भी उठ चुका है? लेकिन अब जिस तरह से पांच राज्यों के चुनाव में इंडिया के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं उससे गठबंधन के भविष्य और कांग्रेस की आगामी भूमिका को लेकर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। एक स्थापित सत्य है कि राजनीतिक दलों का गठन ही एक दूसरे के विरोध में होता है। उनकी एकता तो तत्कालिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। 2014 में जिन मुद्दों पर सत्ता बदली थी उनकी आज व्यवहारिक स्थिति क्या है यह अधिकांश लोग भूल चुके हैं। लेकिन 2014 के बाद क्षेत्रीय दलो की स्थिति क्या रही और कितने अपने राष्ट्रीय स्तर को बचाये रख पाये हैं यह सामने है। 2014 के बाद के बाद कितने लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये कितने छोटे दल एनडीए के साथ जाकर मिले और बाद में अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए एनडीए से बाहर भी आ गये यह सब एक साथ सामने रखना राजनीतिक विश्लेषण के लिये आवश्यक है। इसी विश्लेषण के आधार पर विपक्षी के बने रहने पर सवाल उठाया था। इन राज्यों के चुनाव अधिसूचित हो जाने के ई.डी. और दूसरी एजैन्सियां सक्रिय हुई और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जिस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे थे और फिर जिस तरह का फैसला आया उससे भी स्पष्ट हो गया था कि इस परिदृश्य में विपक्षी एकता की व्यवहारिक कल्पना करना संभव नहीं हो सकता। विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया के घटक दल ही जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि आज सतारूढ़ सरकार और अन्य दलों का एकमात्र विरोध ही कांग्रेस से है। इस समय देश जिस मुकाम से गुजर रहा है उसमें आज भी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दवा करने वाले देश में 80 करोड़ जनता अपने दम पर अपने दो वक्त के खाने का प्रबन्ध नहीं कर सकती। उसे सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय और कर्ज के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि यह आये कुछ हाथों में ही केंद्रित होकर रह गई है। यह कर्ज ही है जो एक भीख मांगने वाले तक भी पहुंचा है क्योंकि वह भी अप्रत्यक्ष में कर अदा कर रहा है। देश की आर्थिकी का यह सच कितनी देर तक आम आदमी से छिपा रहेगा यही आज का बड़ा सवाल है। यह सच राजनीतिक चकाचौंध और मुफ्ती के दावों वायदों से निकलकर जिस दिन आम आदमी के सामने खड़ा हो जाएगा उस वक्त सत्ता परिवर्तन के लिये किसी अन्ना आंदोलन और भ्रष्टाचार के 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं इज़ाद करना पड़ेगा। इस समय देश में यह सब मौजूद है केवल उसे जनता के सामने रखने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता कोई इंडिया का गठबंधन पूरी नहीं करेगा। इसके लिए कांग्रेस को अकेले चलना पड़ेगा। क्योंकि गरीबी बेरोजगारी और महंगाई से देश का बहुमत बुरी तरह त्रस्त है और रोष से भरा हुआ है। इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बहुमत की उम्मीद बनते जा रहे हैं। क्योंकि यही लोग शीर्ष पर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आरबीआई और सी.ए.जी. की रिपोर्टो से इनका समर्थन हो रहा है। इस समय कांग्रेस को अकेला ही चलना पड़ेगा और पारिस्थितियां भी वैसे ही निर्मित हो रही है। इस समय कांग्रेस की सरकारों को अव्यवहारिक चुनावी वायदों से बचना होगा। कर्ज लेकर घी पीने की प्रथा पर लगाम लगानी होगी अन्यथा कांग्रेस भी दूसरे दलों की पंक्ति का हिस्सा बनकर रह जाएगी।

आपसी युद्ध नहीं प्राकृतिक आपदाओं से लडने का वक्त, भारत-चीन ने दिखाया रास्ता

गौतम चौधरी

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर नेपाल और अफगानिस्तान तक की धरती गितत एक महीने से डोल रही है। यह आसन्न बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इस डर से कराके की ठंड में भी नेपाल और अफगानिस्तान के लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को अभिशप्त हैं। लगातार धरती के डोलने से हजारों लोगों की जान चली गयी है और लाखों परिवारों का आशियाना बिखड़ गया है। लेकिन हम युद्ध में व्यस्त हैं। दूरदर्शन की विभिन्न वाहिनियां क्रिकेट मैच की तरह इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध का लाइव दिखा रही है। दुनिया भर के देशों में कहीं फिलिस्तीन तो कहीं इजरायल के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है। मुस्लिम देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान को कोई देखने वाला नहीं है। उलटे इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान की सेना अपने देश में बसे लाखों अफगान शर्नार्थियों को खदेर कर स्वदेश लौटा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारत और चीन ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अफगानियों को नकद सहायता भेजी है। इधर भारत ने भी नेपाल को सहायता उपलब्ध कराई है। यही नहीं इन दोनों देशों ने युद्ध से तबाह हो रहे फिलिस्तीन को भी मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। इससे दुनिया के देशों को सीख लेनी चाहिए।

विगत एक महीने से पर्वतराज हिमालय अप्रत्याशित तरीके से संवेदनशील हैं। कभी अफगानिस्तान तो कभी नेपाल में रह-रह कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालिया भूकंप के कारण जहां एक ओर अफगानिस्तान में चार हजार से ज्यादा लोगों की जान गयी है वहीं नेपाल में मरने वालों की संख्या 400 से अधिक बताई जा रही है। नेपाल और अफगानिस्तान दोनों पहारी मुल्क है और दोनों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सर्दियां बढ़ने के साथ ही, अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद बेघर हुए लोगों में निराशा घर कर रही है। अफगानिस्तान में रात के वक्त ठंड बढ़ रही है। भूकंप के बाद तंबुओं वाला जो कैंप बनाया गया है, उसमें भीड़भाड़ की वजह से छूत की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इन कैंपों में लोग मानवीय सहायता की आस लगाए बैठे हैं लेकिन पूरा इस्लामी जगत इजरायल और फिलिस्तीन के युद्ध पर धरना व प्रदर्शन में व्यस्त है। शेष दुनिया भी इस क्रूर तमाशे में शामिल है।

मानवीय सहायता से जुड़े मामलों पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का कहना है कि अफगानिस्तान में अक्तूबर की शुरुआत में आये भूकंपों की वजह से, हेरात इलाके में 1,54,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय मीडिया में छपी खबरें बताती हैं कि इस आपदा में 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के कारण घायलों को, जिनमें बहुत सी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है। यहां बहुत सारे घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। आटे और पानी जैसी आवश्यकता की चीजों का यहां घोर अभाव है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के शुरुआती मूल्यांकन में पता चला कि इस आपदा में 40 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र ध्वस्त हो गए और इस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलनों के कारण बाकियों के ढहने का संकट लगातार बना हुआ है, जिससे मरीजों की देखभाल मुश्किल हो रही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अफगानिस्तान के 1,14,000 लोगों को तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत है। इसमें से 7,500 गर्भवती महिलाएं हैं, जिनमें से कई औरतों के परिवार वाले हादसे में मारे गए। भूकंप के वक्त बहुत सारी महिलाएं घर पर थीं, जबकि पुरुष खेतों में या जानवरों की देखभाल के लिए बाहर थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप के प्रभावितों में 90 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। यूनिसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं।

इधर देश पर अभी हाल ही में कब्जा करने वाले तालिबान लड़ाकों ने भूकंप से आयी तबाही को अपने हित में उपयोग करने के फिराक में हैं। इस मामले में कई विदेशी एजेंसियों ने दावा किया है कि भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए जो पैसे अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं उससे तालिबान सरकार बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की फिराक में है। इस पैसे से अफगानिस्तान ने ईरान और रूस से घातक हथियार मगाने की योजना बना रहा है। हालांकि, भूकंप की तबाही पर तालिबान के सदस्य और प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान ने सहायता देने के लिए एक कमिशन गठित किया है, ताकि सभी को बराबरी से मदद दी जा सके। इस कमिशन की जिम्मेदारी है कि मदद बांटने में भ्रष्टाचार न हो और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। अफगानिस्तान के भीतर और बाहर मदद में लगे कार्यकर्ताओं को शक है कि इस्लामिक कट्टरपंथी गुट तालिबान इस संकट का सामना करने में अक्षम है। देश से बाहर रहने वाले अफगान नागरिक अपने संबंधियों और दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि उनके द्वारा प्रदत्त मदद की राशि कहीं कट्टरपंथियों के हाथ न लग जाए, जिससे वे मानवीय सहायता के बदले हथियार खरीद लें और मानवता के समक्ष खतरा पैदा करें। तालिबान के राज में मानवाधिकार हनन के चलते न सिर्फ अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाये हैं, बल्कि देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की व्यवस्था, स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान में मानवता की सहायता करने वाला न तो पश्चिमी देश है और न ही इस्लाम के नाम पर दुनिया को एक करने वाले धनी इस्लामिक देश।

जो हाल अफगानिस्तान का है कमोबेस नेपाल का भी वही हाल है। नेपाल भी विगत कई दशकों से गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। विगत दिनों पश्चिमोत्तर नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। हालिया भूकंप के कारण नेपाल में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गयी है। कई हजार परिवारों का आशियाना ध्वस्त हो गया है। नेपाल में भी मानवीय सहायता पहुंचाने वाली एजेंसियां सकते में है। यहां भ्रष्टाचार के कारण परेशानियां उत्पन्न हो रही है।

कुल मिलाकर हालिया भूकंप के कारण हजारों लोगों की मौत हो गयी और लाखों का आसियाना बिखड़ गया है बावजूद इसके दुनिया की मीडिया इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मानवीय सहायता के नाम पर भारत और चीन ने अपना कदम बढ़ाया है जो न तो इस्लामिक देश है और मानवता की दुहाई के लिए अपनी पीठ थपथपाने वाला पश्चिमी जगत। जिस प्रकार जलवायु में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और धरती अशांत हो रही है, वैसे में आने वाला समय मानवता के लिए घातक साबित होगा। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हमें निवटने के लिए आपसी वैमनस्यता को भुलाकर मानवता के कल्याण के लिए काम करने की जरूरत है।

मशरूम की खेती कर सशक्त हुई हिमाचल की महिलाएं

शिमला। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका वाणिकी परियोजना से पहाड़ की महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में मशरूम की खेती करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद की जा रही है। बताया गया कि 65 स्वयं सहायता समूह ने एक वर्ष के अतंराल में 12 लाख से अधिक की कमाई की।

यह अपने आप में रिकार्ड भी है। हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना प्रदेश के 18 वन मंडलों के 32 फोरेस्ट रेंज में प्रोजेक्ट के माध्यम से मशरूम की खेती की जा रही है। जाइका के माध्यम से प्रदेश के 65 स्वयं सहायता समूहों को हर मौसम में मशरूम की खेती करने के तरीके बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बटन मशरूम, शिटाके मशरूम और ढिंगरी मशरूम से आज महिलाओं के साथ-साथ पुरूष भी आजीविका कमा रहे हैं। शिमला के कांडा में स्वयं सहायता समूह को उनके गांव में जाइका वानिकी परियोजना के कर्मचारियों और विशेषज्ञों द्वारा बटन मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रुप ने किराए के कमरे में 10 किलोग्राम के 245 बीज वाले कम्पोस्ट बैग के साथ बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बटन मशरूम के उत्पादन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई। जिस वजह से 25 दिनों के बाद बटन मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ और एक हफ्ते में ग्रुप ने 200 किलोग्राम मशरूम तैयार किया, जो 150 से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर मिल रहा है। बटन मशरूम के साथ-साथ ढींगरी और शिताके मशरूम की प्रजातियों की ज्यादा मांग है। इसको ध्यान में रखते हुए समूह में मशरूम उगाने में विविधता लाने के प्रयास जारी है। जिला मंडी के सुंदरगनर के वन मंडल सुकेत में 19 स्वयं सहायता समूह हैं, जो मशरूम की खेती कर आजीविका कमा रहे हैं। बताया गया कि इन सहायता समूह ने पिछले एक साल में आठ लाख रुपये की कमाई की है। जाइका की ओर से मशरूम की ट्रेनिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर कृषि विज्ञान केंद्रों की सेवाएं ली जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 65 में से 59 ऐसे ग्रुप हैं, जो पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से महिलाओं के 45 ग्रुप और ग्रुप पुरूष के हैं, जबकि 12 ग्रुप महिला एवं पुरूष का मिश्रण हैं। गौरतलब है कि जाइका प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में लोगों को आजीविका कमाने का बेहतर मौका मिल रहा है। इसके माध्यम में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने एवं हर मौसम में अलग-अलग किस्म के मशरूम तैयार करने के लिए कलस्टर तैयार किया जा रहा है।

जिला शिमला के जुब्बल रेंज के तहत शक्ति स्वयं सहायता समूह ने एक दिन में 20 किलोग्राम मशरूम तैयार किया। यह बटन मशरूम है और 170 रूपये प्रति किलो के हिसाब में इसकी कीमत मिल रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गत बुधवार को 20 किलोग्राम मशरूम तैयार किया। ऐसे में जाहिर है कि मशरूम की खेती कर आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी आर्थिकी को और भी मजबूत कर रही हैं।

जाइका प्रोजेक्ट के माध्यम से आज हिमाचल की महिलाएं अपनी आर्थिकी में सुधार करने लगी हैं। स्वयं सहायता समूहों के तहत जुड़े ऐसी महिलाओं ने बटन मशरूम, शिकटाके मशरूम और ढिंगरी मशरूम की खेती कर अच्छी कमाई कर रही हैं। प्रदेश में हर मौसम के मुताबिक तैयार होने वाले मशरूम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।

कृषि योजनाएं बनीं दुनी चंद के लिए वरदान

शिमला। जिला मंडी के पधर उपमंडल के गांव मसेरन के दुनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती से एक साल में ही 3 लाख की कमाई कर ली। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड से 2020 में सेवानिवृत

होने के बाद पेंशन न होने के कारण जब उनके पास परिवार के भरण-पोषण का कोई जरिया न रहा तो वह खेती करके आय का स्रोत ढूंढने लगे। परन्तु बंदरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण इसमें सफल नहीं हो पाए। ऐसी मायुसी में जब उन्हें एक किसान जागरूकता शिविर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने खेतों की बाड़बंदी के लिए कृषि विभाग के पास आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकार होने पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी हो गई। इसके उपरांत खेती का कार्य शुरू करने पर उन्होंने पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से एंटी हेलनेट लगवाया और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉलीहाऊस भी लगवा लिया। दुनी चंद ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसी जमीन पर जिस पर खेती करने से कोई कमाई नहीं हो रही थी, से एक साल में ही 3 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर ली। उन्होंने पॉलीहाऊस में विभिन्न बेमौसमी, एंटी हेलनेट में मौसमी सब्जियां तथा खेतों में गेहूं, कोदरा, माह और मक्की की खेती की। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने पांच लोगों को रोजगार भी दिया।

दुनी चंद ने बताया कि वह कृषि विभाग से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस योजना और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेकर खेती कर रहे है। इससे पहले खेती से कोई आय नहीं हो रही थी, लेकिन कृषि विभाग की योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हुई हैं। वर्तमान में उन्होंने पॉलीहाऊस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च लगाई हुई है। नेट के अन्दर टमाटर लगाया है। खेत में तैयार सभी सब्जियां व अन्य फसलें खेत में ही बिक जाती हैं।

दुनी चंद ने खेती से अच्छी आय होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अपनाने से खेती करके अच्छी आय अर्जित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने किसानों, बागवानों और बेरोजगारों से अपील करते हुए कहा कि वे कृषि विभाग की स्कीमों को अपनाकर उनका भरपूर फायदा उठाएं। इससे वे मेरी तरह अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं।

द्रंग के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ पूर्ण चंद ने बताया कि 2022-23 में द्रंग विकास खण्ड के किसानों को कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत 17 लाख रुपये, मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस योजना पर 28 लाख रुपये और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना पर 55 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। दुनी चंद को इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत 4,47,887 का अनुदान दिया गया।

वहीं कृषि उप निदेशक मंडी राजेश डोगरा ने बताया कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाओं का चला रखी हैं ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अच्छी खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकें।

उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वे रोजगार मांगने वाले न बनकर दूसरों को रोजगार देने वाले बने।

जल दिवाली-'महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान' शुरू किया गया

शिमला। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपनी प्रमुख योजना - अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एएमआरयूटी) के तहत एक प्रगतिशील पहल 'महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान' को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना में मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की भी भागीदारी है। ओडिशा अर्बन एकेडमी इसकी 'नॉलेज पार्टनर' है। इस 'जल दिवाली' अभियान का जश्न 7 नवंबर, 2023 से शुरू होकर 9 नवंबर, 2023 तक जारी रहेगा।

इस अभियान का उद्देश्य जल शासन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उन्हें अपने-अपने शहरों में जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) के दौरे के माध्यम से जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। संयंत्रों के दौरों से उन्हें घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी जो यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को अपेक्षित गुणवत्ता का जल उपलब्ध हो। इस अभियान का व्यापक लक्ष्य जल बुनियादी ढांचे के प्रति महिलाओं में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को विकसित करना है।

भारत में 3,000 से अधिक जल उपचार संयंत्र हैं, जिनकी निर्मित जल उपचार क्षमता 65,000 एमएलडी से अधिक और परिचालन क्षमता 55,000 एमएलडी से अधिक है। इस अभियान के दौरान, महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगे, जिनकी संयुक्त परिचालन क्षमता 20,000 एमएलडी (देश की कुल क्षमता की 35 प्रतिशत से अधिक) से अधिक है।

घरेलू जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। महिलाओं को जल उपचार और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का लक्ष्य उनके घरों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में उनकी क्षमता को बढ़ाना है। इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता के मुद्दों को हल करना है।

महिलाओं के लिए जल, जल के लिए महिलाएं अभियान, 'जल दिवाली' के पहले चरण में राष्ट्रव्यापी रूप से 15,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी के साथ सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (आदर्श आचार संहिता के तहत 5 राज्यों को छोड़कर) की भागीदारी रहेगी। इस अभियान के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं।

महिलाओं को जल उपचार संयंत्रों और जल परीक्षण सुविधाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराना

महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों और वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं की समावेशिता और भागीदारी को बढ़ावा देना

महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना

इस अभियान के अपेक्षित परिणामों में जल उपचार के बारे में जागरूकता और जानकारी में वृद्धि करना, स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, सकारात्मक सामुदायिक प्रभाव और भविष्य की पहल के लिए मॉडल शामिल हैं।

'अमृत' (एएमआरयूटी) और एनयूएलएम से राज्य और शहर के अधिकारी डब्ल्यूटीपी की पहचान करके इन यात्राओं को सुविधाजनक बनाएंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य और शहर के अधिकारियों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका समर्थन करने का आहवान किया है। यह पहल 'अमृत' के तहत जल बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

महामाया स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाओं ने दो महीने में कमाये 2 लाख रुपये

शिमला। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र और आजीविका सुधार परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को घरद्वार पर प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित व जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग की जायका वानिकी परियोजना इस परियोजना से मंडी जिला के सुकेत वन मंडल में वन परिक्षेत्र सुकेत में ग्राम वन विकास समिति भँगलेरा तहसील सुन्दरनगर के महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बैग बनाकर और कपड़े सिलाई करके अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। महामाया स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण के बाद दो महीनों में ही लगभग 2 लाख रुपए धनराशि कमा चुकी हैं। समूह की महिलाओं को जायका वानिकी परियोजना के अर्न्तगत वन विभाग के माध्यम से 28-28 दिन की कपड़े की सिलाई तथा बैग बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने जूट से लंच बैग, बोतल बैग, फाइल बैग आदि बनाने की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण लेने के उपरांत महिलाएं बैगों को दुकानों, स्कूलों, मेलों में बेचती है तथा ऑर्डर पर भी बैग बनाती हैं। महिलाएं 100 रुपये लेकर 500 रुपए तक के बैग बनाती हैं। साथ ही गांव व आसपास के क्षेत्र की महिलाओं के सूट की सिलाई घर पर ही करती हैं।

समूह की सदस्य राधा ने बताया कि वह महामाया समूह से सहायता समूह की एक सदस्य है। वन विभाग जाइका की तरफ से उसे बैग बनाने और सूट सिलाई की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है। वन विभाग जाइका की तरफ से उसे विभिन्न जिलों में ट्रेनर के रूप में जाने का भी मौका मिला है जो कि उसके लिए एक रोजगार का साधन बना हुआ है जिसके लिए उसने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया।

डीएफओ सुकेत राकेश कटोच ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताया जा रहा है कि समूह के माध्यम से महिलाएं किस प्रकार जायका द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकती है। महिलाओं को स्वरोजगार पर बल देकर और स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को समूह को आगे बढ़ने एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं घर बैठे काम कर आर्थिकी को मजबूत करने में जुटी हैं।

क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी के सरगनाओं पर होगी कड़ी कारवाईः मुकेश अग्निहोत्री

शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी की जांच सम्बंधी एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी के माध्यम से कम समय में अधिक लाभ का झांसा देकर प्रदेश के भोले-भाले लोगों को सुनियोजित तरीके से ठगा गया है।

प्रदेश में 2500 करोड़ रुपये के अवैध निवेश से जुड़ी क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त करते हुए उप-मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अनाधिकृत योजनाओं में निवेश न करें। उन्होंने कहा कि नियमन के अभाव में निवेशकों को ऐसे निवेश से धोखाधड़ी और हेराफेरी का जोखिम बना रहता है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग फोरलेन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से मिले मुआवज़े का पैसा भी क्रिप्टो करेंसी में लगा कर डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बने। उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहते हुए इस तरह की धोखाधड़ी वाली योजनाओं के झांसे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी के झांसे में आकर लोगों की मेहनत की कमाई के लगभग 500 करोड़ रुपये डूब गए हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में प्रमाणिकता के संबंध में अस्पष्टता की पुष्टि की है। राज्य के विभिन्न जिलों से क्रिप्टो धोखाधड़ी की शिकायतें निरंतर सामने आ रही हैं। अब तक क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी की 300 से अधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। इसके सरगनाओं ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस क्रिप्टो करेंसी सरगनाओं के खिलाफ उचित कारवाई कर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाएगी।

उप-मुख्यमंत्री ने क्रिप्टो नेटवर्क को तोड़ने और मंडी से आरोपी हेमराज और सुखदेव, ऊना से अरुण गुलेरिया और अभिषेक सहित कई गिरफ्तारियां करने के लिए हिमाचल पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के सरकाघाट का एक अन्य आरोपी सुभाष शर्मा शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

पुलिस महानिदेशक, संजय कुंडू ने बताया कि विभाग ने क्रिप्टो घोटाले में संलिप्त लगभग 2.5 लाख अलग-अलग आईडी वाली वेबसाइटों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी के इस जाल में आरम्भिक स्तर पर 70 से 80 धोखेबाज शामिल होने का अनुमान है। पुलिस ने धोखेबाजों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर हिमाचल और जीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर अब तक 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और गृह मंत्रालय ने भी हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।

उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अनियत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 के तहत कारवाई की जा रही है। इस अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है।

क्रिप्टो डिजिटल घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल के प्रमुख एवं डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर ने मामले पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी भी उपस्थित थे।

चिंतपूर्णी मंदिर रोप-वे निर्माण पर व्यय होंगे 76.50 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विशेषतौर पर राज्य में स्थित शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं व अन्य पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही इन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऊना जिला में स्थित विश्व विख्यात चिंतपूर्णी मंदिर के लिए रोप-वे निर्माण पर 76.50 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

लगभग 1.1 किलोमीटर लम्बे इस रोप-वे का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार त्वरित कदम उठा रही है। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घण्टा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की अहमियत के दृष्टिगत इस पर विशेष बल दे रहे हैं। उनका मानना है कि चिन्तपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक एवं अध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है। वर्तमान में इस मंदिर को बाबा माईदास भवन पार्किंग क्षेत्र से सिंगल लेन सड़क से जोड़ा गया है। नवरात्रों सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भारी भीड़ और यातायात जाम इत्यादि जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत रज्जू मार्ग की परिकल्पना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति के भी अनुकूल है।

चिन्तपूर्णी मंदिर में इस रज्जू मार्ग प्रणाली के स्थापित होने से भीड़ नियंत्रण में सुविधा होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम मार्ग भी उपलब्ध हो सकेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस पवित्र स्थल तक लोगों की यात्रा सुगम्य एवं आरामदायक होगी। इसके साथ ही देश के मुख्य धार्मिक स्थलों में भी यह प्रमुखता से शामिल हो सकेगा।

मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में धार्मिक पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है और यहां के प्राचीन मंदिर व शक्तिपीठों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इन शक्तिपीठों व अन्य धार्मिक स्थलों में आधारभूत ढांचे के विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। श्रद्धालुओं की यात्रा को अविस्मरणीय एवं आरामदायक बनाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। चूंकि पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से स्थानीय युवाओं के रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 1 करोड़ 59 लाख 60 हज़ार 548 रुपये की सहायता राशि जारी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। प्रत्येक व्यक्ति को घर के समीप सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की जा रही हैं। वहीं, जरूरतमंद लोगों को गम्भीर रोगों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष इस दिशा में सार्थक सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन जरूरतमंद गरीब लोगों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत किया गया है। इसमें ओ.पी.डी. तथा अन्य सम्बद्ध व्यय भी शामिल हैं। लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है। कैंसर, मुख्य हृदय रोग शल्य चिकित्सा, एएसडी, वीएसडी, वॉल्व प्रतिस्थापन व बाईपास सर्जरी, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी शल्य चिकित्सा, गुर्दे के प्रत्यारोपण सहित ब्रेन सर्जरी जैसी गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।

पात्र लाभार्थी प्रदेश में स्थित सभी राजकीय अस्पतालों सहित पी. जी.आई. चण्डीगढ़, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, सैक्टर-32 चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में भी उपचार पर इस कोष के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत 01 जनवरी, 2023 से लेकर अब तक 1 करोड़ 59 लाख 60 हजार 548 रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 57 लाभार्थियों को 35 लाख 15 हजार 548 रुपये की राशि उनके खातों में भेजी गई है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 24 लाख 45 हजार रुपये की राशि सम्बंधित अस्पतालों को जारी की गई है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण-पत्र, अनुमानित उपचार लागत, उपचार उपरान्त आवेदन की स्थिति में सत्यापित मूल बिलों की प्रतियां, फोटो पहचान-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति इत्यादि दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त अथवा स्थानीय विधायक के माध्यम से भी चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार द्वारा प्रदेश में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उपचार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत भी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कोष के माध्यम से 01 जनवरी, 2023 से अब तक 26 लाभार्थियों को लगभग 75 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक आधुनिक एवं सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना एक कल्याणकारी राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए ज़रूरतमंदों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ कर वहां डॉक्टर

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज़िला मंडी के करसोग क्षेत्र में अलसिंडी के पास हुई सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता और घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है।

सेब के साथ स्थानीय फसलों का करें समावेश

शिमला/शैल। कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर की 18वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने की जिन्होंने इस बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

यह बैठक आगामी वर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का रोडमैप तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी। सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि क्षेत्र के किसान नए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति बहुत ग्रहणशील हैं। फसल गहनता और विविधीकरण के महत्व पर बोलते हुए प्रोफेसर चंदेल ने सेब की खेती के साथ स्थानीय श्री अन्न की किस्मों का समावेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों के खेतों में एक्सपोजर विजिट की योजना बनाई जानी चाहिए और केवीके को विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के मॉडल विकसित करने चाहिए, जहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सके।

निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. इंद्र देव ने विश्वविद्यालय की विस्तार गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सुझाव दिया कि केवीके की विभिन्न पहलों का प्रभाव विश्लेषण किया जाना चाहिए और सकारात्मक परिणामों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने समुद्र तल से 1800 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर सीडलिंग रूटस्टॉक पर उच्च घनत्व वाले सेब बगीचों पर अनुसंधान परीक्षण स्थापित करने की केवीके की पहल की सराहना की। उन्होंने वैज्ञानिकों से इन परीक्षणों से नियमित रूप से वैज्ञानिक डेटा रिकॉर्ड करने का आग्रह किया।

आईसीएआर अटारी जोन-I के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजेश राणा ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनों का सुझाव दिया। उन्होंने उन्नत कृषि उपकरणों के लिए एक कस्टम हायरिंग सेंटर का भी प्रस्ताव रखा। देश के विभिन्न केवीके के साथ क्रॉस-लर्निंग कार्यक्रम और संबंधित विभागों के साथ संयुक्त प्रयास का भी सुझाव डॉ. राणा द्वारा दिया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के डॉ. आलोक कुमार ने आलू पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन स्थापित करने का सुझाव दिया। सदस्यों का विचार रहा कि महिलाओं के सतत विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए। सभी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवीके के विभिन्न प्रयासों की भी सराहना की।

इससे पहले केवीके के समन्वयक डॉ. अशोक ठाकुर ने कृषि विज्ञान केंद्र की प्रगति रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए नियोजित गतिविधियों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि कैसे स्टेशन ने फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए उच्च घनत्व वाले सेब प्रबंधन में कैनोपी प्रबंधन के लाभों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया है। डॉ. ठाकुर ने यह भी बताया कि कैसे स्टेशन ने सेब मोनोकल्चर से निपटने के लिए उच्च मूल्य वाली सब्जियों के साथ अंतर फसल की शुरुआत की है। बैठक के दौरान सदस्यों ने राय दी कि कृषि को एक करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए केवीके को नवीन कार्यक्रमों के साथ स्कूली बच्चों और युवाओं तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। लाइन विभागों के अधिकारियों ने विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण में केवीके का समर्थन मांगा।

राजभवन में मनाया गया विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन शिमला में आयोजित आंध्र प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुंडुचेरी, तमिलनाडु व पंजाब राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न राज्यों के लोगों में आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता की भावना को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत-श्रेष्ठ भारत परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस को मनाने की परम्परा आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक किसी भी प्रदेश, समुदाय व जाति व धर्म से संबंध रखते हों लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना सबसे महत्त्वपूर्ण है। देश प्रेम व देश भक्ति की भावना के प्रति समाज के सभी वर्गों की संवेदनशीलता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपसी मेल-जोल और सदभाव से न केवल हमें एक-दूसरे की संस्कृति व रीति-रिवाजों को समझने और जानने का अवसर प्राप्त होता है बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बल मिलता है।

इस अवसर पर केरल, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

केरल के निवासी एवं भारतीय वन सेवाएं के वरिष्ठ अधिकारी रवि शंकर ने तबला वादन तथा उनकी पत्नी रजीशा ने मधुर संगीत की प्रस्तुति दी। पंजाब सहायक कमांडर पद पर तैनात राजेन्द्र कुमार ने भी संगीत पर आधारित मनभावन प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुंडुचेरी, तमिलनाडु व पंजाब के नागरिकों ने भाग लिया।

राज्यपाल ने सेंट बीड्स महाविद्यालय शिमला, ललित कला महाविद्यालय शिमला तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी शिमला के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 31-31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल के योगदान को याद किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक रिज में

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिवंगत इंदिरा गांधी द्वारा देशहित में लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों को भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। वह 'आयरन लेडी' के रूप में न केवल भारत अपितु विश्वभर में विख्यात हैं।

राज्यपाल ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि आज 31 अक्तूबर को लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है। इस दिवस को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की उपलब्धियों को देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की छोटी-छोटी रियासतों को एकजुट कर वृहद भारत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर, नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, अन्य पार्षदगण, उपायुक्त आदित्य नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना

शिमल/शैला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी एवं रोक के दृष्टिगत विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं।

उन्होंने कहा कि बिना बिल, चालान अथवा ई-वे-बिल के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घाटे का एक बड़ा कारण बनता है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि में भी इसका उल्लेख नहीं हो पाता।

उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग ने 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण किया और अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उनसे वस्तु एवं सेवा कर कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके दृष्टिगत कर चोरी करने वालों के विरूद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

प्रवक्ता ने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है। कोई भी व्यक्ति टॉल-फ्री दूरभाष नम्बर 1800-180-8060 अथवा व्हट्सऐप नम्बर 9418331426 पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की प्रवेश, काउंसलिंग तथा पंजीकरण प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

शिमला/शैल। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकारी सेवाओं का सरलीकरण सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अपनी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन की हैं।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रदेश में स्थित बहुतकनीकी संस्थानों, फार्मेसी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। बोर्ड द्वारा बहुतकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र व छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया, काउंसलिंग तथा पंजीकरण प्रक्रिया को वैब आधारित मॉडयूल के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस वैब आधारित मॉडयूल के माध्यम से अब छात्र-छात्राएं अपने परीक्षा फार्म तथा पुनर्मूल्यांकन फार्म भी ऑनलाईन माध्यम से भर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इस मॉडयूल के माध्यम से सभी सरकारी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के सत्रीय और प्रायोगिक अंक भी ऑनलाइन ही बोर्ड में जमा किए जा सकते हैं।

बोर्ड द्वारा माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी अब ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की वैबसाइट पर इसके लिए आवेदन तथा निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं। बोर्ड द्वारा सभी सरकारी व निजी बहुतकनीकी संस्थानों को सम्बद्धता जारी करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ ही पाठयक्रम को रोज़गारपरक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2023-24 से कई मूल्यवर्धित पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें रोबोटिक्स, ब्लॉक-चेन टैक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डॉटा एनालिटिक्स, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठयक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलेक्ट्रिक व्हीकल मकैनिक, मैंटेनेंस मकैनिक, सोलर टेक्निशियन, ड्रोन टैक्निशियन, मैक्ट्रोनिक्स तथा इंटरनेट ऑफ थिंगज़ टैक्निशियन के कोर्स आरम्भ किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री का मानना है कि बदलते परिवेश के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना समय की मांग है। प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस व सार्थक कदम उठाते हुए प्रदेश के विकास में युवा ऊर्जा के योगदान व दोहन की दिशा में आगे बढ़ रही है।

राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ाई गई

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवम्बर, 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 अक्तूबर, 2023 तक निर्धारित की गई थी।

उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई है।

विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो, इसके दृष्टिगत प्रदेश भर में ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सयमबद्ध पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।

उप-चुनाव में मतदान के लिए 5 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश घोषित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जिला सोलन की नगर पंचायत अर्की के नगर परिषद वार्ड नम्बर 2 मियांपुर और ज़िला शिमला की नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नम्बर 6 छावनीवीर हॉस्पिटल में होने वाले उप-चुनावों के दृष्टिगत 5 नवम्बर, 2023 को सवैतनिक अवकाश (मतदान होने की स्थिति में) घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें सम्बंधित संस्थानों के उप-चुनाव में मतदान करना है। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

केन्द्र के असपष्ट पत्रों से उलझा हाटी मामला

एक वर्ष में स्थिति स्पष्ट न कर पाना राज्य सरकार की असफलता

शिमला/शैल। हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र के हाटियों को पचास वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद भारत सरकार द्वारा संसद में संशोधन लाकर जो जनजातिय का दर्जा दिया था उसकी अनुपालना करवाने के लिए भी हाटी समुदाय को आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। 154 पंचायतों के तीन लाख हाटीयों को आन्दोलन का रास्ता इसलिये अपनाना पड़ा है कि 2022 में भाजपा शासन के दौरान केन्द्र ने संविधान संशोधन करके हाटीयों को जनजातिय का दर्जा दिया था। लेकिन राज्य सरकार इस पर अब तक अमल करने के आदेश जारी नहीं कर पायी है। सरकार के अनुसार जो संशोधन राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित होकर आया है उसमें कहा गया है कि गिरीपार रहने वाले सभी लोगों को जनजातिय का दर्जा हासिल होगा। लेकिन संबद्ध मन्त्रालय के अवर सचिव से जो पत्र राज्य सरकार को मिला है उसमें इस क्षेत्र में रहने वाले एस सी समाज को इससे बाहर रखा गया है। इसी के साथ केन्द्र की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस फैसले को लागू करने का आधार वर्ष क्या होगा।

ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन बिन्दुओं पर केंद्र सरकार से कोई स्पष्टीकरण आये बिना इस फैसले को लागू किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि ऐसे मामलों में एक आधार वर्ष तो तय किया ही जाता है। जो केन्द्र ने न तो राष्ट्रपति को भेजे और न ही संसद से पारित संशोधन में स्पष्ट किया है तथा न ही अवर सचिव द्वारा भेजे गये पत्र में। स्मरणीय है कि गिरी पार क्षेत्र के लोगों द्वारा जनजातीय दर्जा दिये जाने का मुद्दा 1967 में जौनसार बाबर को यह दर्जा मिलने के बाद उठाया जाना शुरू हुआ। क्योंकि दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां एक जैसी थी। विकास के नाम पर यह क्षेत्र पिछड़े हुये थे। जातिवाद और देव दोष जैसी संस्कृति से जकड़े हुये थे। खाप पंचायतों की तर्ज पर खुम्बली के फैसलों से बंधा समाज था। लेकिन आज जब 2023 में इनको जनजाति का दर्जा दिया जा रहा है तब आधा शतक पहले की परिस्थितियां नहीं है। अब तो शायद दूसरे क्षेत्रों के लोग भी वहां के निवासी हो गये है। ऐसी वस्तुस्थिति में फैसले पर अमल के लिए एक आधार वर्ष चिन्हित होना आवश्यक है। दूसरी ओर जब वहां के रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी जनजाति करार दे दिया गया तब उसमें रोष होना स्वभाविक था। क्योंकि 1950 में अनुसूचित जाति और जनजाति का फैसला और वर्गीकरण हो गया था। इसके अनुसार अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत आरक्षण हासिल है जो इस क्षेत्र के इन लोगों को हासिल है। परन्तु अब उन्हें भी जनजाति घोषित कर दिये जाने से उनके इस अधिकार में कटौती हो रही है। इसके लिये गिरी पार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के मंच तले प्रदेश उच्च न्यायालय में केन्द्र के फैसले को चुनौती दे दी गयी है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के तीन मंत्रालयों को नोटिस जारी कर दिया है। 18 दिसम्बर को यह मामला लगा है। उधर आन्दोलनरत हाटी मंच ने इस फैसले पर दीपावली तक अमल करने के लिए राज्य सरकार को चेतावनी दे दी है। उसके बाद आन्दोलन के उग्र होने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में सुक्खु सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है यह देखना रोचक हो गया है। क्योंकि यह आन्दोलन उस समय आया है जब आगे लोकसभा चुनाव होने हैं।

स्वास्थ्य विभाग दो वर्षों में फाइनल नहीं कर पाया टैण्डर

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सवालों में सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता कंपनियों का भुगतान नहीं कर पा रही कई कंपनीयों ने रोकी सेवाएं

शिमला/शैल। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां सरकार के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही थी उन्होंने अपनी सेवाओं को बन्द करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सरकार उनके बिलों का भुगतान नहीं कर पा रही है। कई कंपनियां सेवाएं बन्द कर चुकी हैं और कई ने काम बन्द करने का अल्टीमेटम दे रखा है। यह आरोप है नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जय राम का। जयराम के मुताबिक कल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रही डायलिसिस सेवाएं सेवा प्रदाता कंपनी ने बंद कर दी है। लोगों को निजी अस्पताल में सेवाएं लेनी पड़ रही है क्योंकि सरकार कंपनी को भुगतान नहीं कर पायी है। इससे जिन लोगों को अब तक निःशुल्क इलाज मिल रहा था उन्हें अब हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिम केयर के तहत ईम्पैनल्ड अस्पतालों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हिम केयर के तहत विभिन्न चिकित्सा सामान उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे आप्रेशन प्रभावित हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट बन्द पड़े हैं। इस तरह प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गयी है।

नेता प्रतिपक्ष की इसी चिन्ता के बीच यह भी सामने आया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 17 – 1 – 2022 के लिए एक टेंडर जारी किया था। इस पर कोई फैसला न हो पाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके 28 – 4 – 2022 के लिये पुनः जारी किया गया और फिर रद्द हो गया। तीसरी बार 8 – 7 – 2022 के लिए जारी किया गया। 19 – 10 – 2022 और 9 – 11 – 2022 को सैंपल और डैमोन्सट्रेशन भी हो गया परन्तु इसके बाद रद्द कर दिया गया। चौथी बार 18 – 5 – 2023 को फिर आमंत्रित हुआ और निविदायें आयी परन्तु फिर रद्द हो गया। पांचवीं बार 14 – 9 – 2023 को आमंत्रित हुआ। इस बार पांच निविदायें आयी। इसमें भी कई निविदा दाताओं के दस्तावेजों पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। इस बार यह टैण्डर फाईनल हो पाता है या नहीं यह रोचक बना हुआ है।

ऐसे में स्वभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि जो विभाग करीब दो वर्ष में एक टैण्डर को फाइनल न कर पा रहा हो वह प्रदेश की जनता को क्या और कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्या इस तरह की स्थिति स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आयी होगी? उनके स्तर पर क्या संज्ञान लिया गया होगा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग यदि कोई खरीद कर रहा होगा तो निश्चित रूप से उसका ताल्लुक आम आदमी के स्वास्थ्य से रहा होगा। यदि ऐसे टैण्डर भी दो वर्ष में फाइनल न हो पाये तो संबंधित विभाग ही नहीं पूरी सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है।

क्या सरकार ऑपरेशन .....पृष्ठ 1 का शेष

तुरन्त प्रभाव से स्थितियों के सक्रिय नियंत्रण में नहीं आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिये कठिनाईयां बढ़ सकती हैं। क्योंकि आरटीआई के माध्यम से कर्ज के आंकड़े बाहर आना एक ऐसा हथियार सिद्ध होगा जिसकी काट किसी के पास नहीं होगी। क्योंकि आने वाले समय में प्रमुखता के यह सवाल पूछा जायेगा कि यह कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है। कर्ज के इस आंकड़े के सामने आपदा के आंकड़े भी छोटे पड़ जायेंगे। जबकि पहले यह कहा गया था कि केन्द्र ने प्रदेश के कर्ज लेने पर ही कटौती लगा दी है।